https://swadeshbhartnews

R.N.I. No. UPHIN/2021/82888

स्वदेश भारत न्यूज

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

जौनपुर से प्रकाशित

जौनपुर
मंगलवार 28 अप्रैल 2026
वर्ष : 05 – अंक : 17
पृष्ठ – 4 मूल्य – 5:00 रूपये

न्यूज कैप्सूल

आप के 7 पूर्व नेता आधिकारिक तौर पर हुए भाजपा सांसद, राज्यसभा के सभापति ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली। राज्यसभा के सभापति ने सदन के उन सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय को मंजूरी दे दी है जो हाल में आम आदमी पार्टी (आप) से अलग हो गए हैं। राज्यसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी सदन में विभिन्न दलों की सदस्य सूची में आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा करने वाले सदस्यों के नाम भाजपा की सूची में आ गए हैं और पार्टी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी से निर्वाचित सदस्य राघव चड्ढा, डॉ संदीप कुमार पाठक और डॉ अशोक कुमार मित्तल ने गत 24 अप्रैल को राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन कर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी। इन सदस्यों में उपरोक्त तीन के अलावा सर्वश्री हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आज जारी सूची के अनुसार इन सदस्यों को 24 अप्रैल से ही भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इस सूची में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गई है। सदन में अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के अलावा दो सदस्य श्री नारायण दास गुप्ता और श्री संत बलबीर सिंह के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने श्री राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप नेता पद से हटा दिया था। उसी के बाद से पार्टी में समस्या उत्पन्न हुई है।

अमृतसर सीमा पर ड्रोन से हेरोइन तस्करी नाकाम, बीएसएफ ने नशा किया बरामद

फिरोजपुर। अमृतसर के अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में रविवार रात सीमा सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली जब बीओपी कलाम डोगर इलाके में ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। देर रात सीमा पर तैनात जवानों ने संदिग्ध ड्रोन की आवाज सुनी और तुरंत अलर्ट होकर कार्रवाई शुरू की। जवानों ने ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए उसकी दिशा में फायरिंग की और पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में खेतों से ड्रोन और करीब 535 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अमृतसर के इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। जैसे ही ड्रोन की आवाज सुनाई दी, जवानों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इलाके की घेराबंदी कर दी। त्वरित कार्रवाई के कारण ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया और तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई। फायरिंग के बाद बीएसएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान आसपास के खेतों और खुले इलाकों से एक ड्रोन बरामद किया गया। इसके साथ ही एक पैकेट मिला जिसमें करीब 535 ग्राम हेरोइन पाई गई, जिसे सुरक्षित जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था।

पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर पर शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की 11 ठिकानों पर छापेमारी

चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने सोमवार को पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। अधिकारियों के मुताबिक पीएमएलए के तहत चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर में कुल 11 ठिकानों को कवर किया गया। ये ठिकाने भुल्लर, उनके सहयोगियों और कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े लोगों से संबंधित बताए जा रहे हैं। ईडी की यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज मामले पर आधारित है। इस मामले में आरोप है कि भुल्लर ने एक आपराधिक केस को सुलझाने के लिए बिचैलिए के जरिए अवैध भुगतान की मांग की थी। साथ ही उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति होने के भी आरोप हैं। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोतों का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाना है।

बंगाल का उत्साह बता रहा, टेरर, माफियाराज व कटमनी की सरकार से मिलेगी मुक्तिः सीएम योगी

लखनऊ (संवाददाता)। प. बंगाल के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें सोमवार को 'वंदे मातरम, भारत मां, जयश्रीराम, हिंदू सम्राट, बुलडोजर बाबा' के जयकारों से गूंज उठीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां भाजपा उम्मीदवार अनुपम विश्वास के लिए चुनावी रथ पर रोड-शो करने निकले तो जैसे जनसमुद्र उमड़ पड़ा। सड़कों पर हजारों युवा एवं बुजुर्ग अपने लोकप्रिय नेता की झलक मोबाइल में कैद करते दिखाई दिए तो छतों पर खड़ीं महिलाएं हाथ जोड़कर 'योगी-योगी' के नारे लगाती दिखीं। बंगाल में 'बुलडोजर बाबा' के नाम से पुकारे जा रहे सीएम योगी ने भी सड़कों पर उमड़े लोगों पर बीच-बीच में पुष्पवर्षा की। सीएम योगी के साथ भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या भी उपस्थित रहे। सीएम योगी के रथ के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, मां सीता, लक्ष्मण व संकटमोचन हनुमान के वेष में कलाकार चल रहे थे। आध्यात्मिक धरा पर इस वेशभूषा में कलाकारों को देख हर कोई उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करता रहा। वहीं पूरे रोड-शो के मार्ग में भगवा व भाजपा का ध्वज फहराता दिखाई दिया। कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में उमड़े जनसैलाब ने एक तरह से सीएम योगी को आश्वस्त किया कि यहां 'भगवान', भगवा व भाजपा के नेतृत्व में आपके विश्वास (भाजपा प्रत्याशी अनुपम विश्वास) की ही जीत होगी। 15 वर्ष से तृणमूल कांग्रेस की अराजकता से परेशान बंगाल के नागरिक सुशासन की आस में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जयश्रीराम का उद्घोष करते दिखे। बीच-बीच में 'वंदे मातरम, भारत मां, हिंदू सम्राट, बुलडोजर बाबा'

की जयकार से गूंज रहे कल्याणी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सीएम योगी से कह रहे थे कि बुलडोजर को दंगाइयों का काल बनाएं। सीएम योगी ने भी आश्वस्त किया कि 4 मई के बाद बंगाल में माफियाराज समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बंगाल के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए रोड शो में उमड़ी भीड़ का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आपका उत्साह बता रहा है कि बंगाल टेरर, माफियाराज और कटमनी की सरकार से मुक्ति पाएगा। 23 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान के रुझान बताते हैं कि बंगाल में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनेगी। सीएम ने कहा कि ममता दीदी गुमराह करती थीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब बंगाल में खेला शेष, उन्नयन शुरू। बंगाल को फिर से उन्नयन-विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए 4 मई को मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने माफिया, करप्शन को समाप्त किया और जो बचा था, उसे बुलडोजर ने पूरा किया। भाजपा सरकार आने के बाद बंगाल में भी माफियाराज समाप्त होगा। आमार सोनार बांग्ला, अब टीएमसी मुक्तो बांग्ला बनेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौराः शिमला पहुंची, राज्यपाल और सीएम समेत अन्य लोगों ने किया जोरदार स्वागत

शिमला।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचीं। शिमला के निकट छराबड़ा स्थित कल्याणी हेलीपैड पर आज उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए राज्य की जनता की ओर से उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (जिन्हें राष्ट्रपति के दौरे के लिए मंत्री-इन-वेटिंग नामित किया गया है), सांसद सुरेश कुमार कश्यप, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. धैय्या सहित राज्य सरकार और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पांच दिवसीय हिमाचल दौरे को लेकर राजधानी शिमला में सुरक्षा के पुख्ता का इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति आज शिमला के रिट्रीट में पहुंचेंगी। सुरक्षा की दृष्टिगत शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी के जवान तैनात हैं। शहर की सड़कों पर दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि यातायात में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। हालांकि संजौली और ढली में सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग के कारण लोगों को पैदल चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीआईपी मूवेंट के दौरान शहर में ट्रैफिक को भी रोका जा रहा है जिस वजह से लोग परेशान हैं। लोक भवन रिट्रीट में राष्ट्रपति आज पहुंचेगी और इसके बाद उनके राजधानी शिमला समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग कार्यक्रम हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण करेंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शिमला के मशोबरा में राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगी। राष्ट्रपति 28 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक भवन, शिमला में आयोजित भोज में शामिल होंगी।

घरेलू और कामर्शियल एलपीजी पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- हमारे पास पर्याप्त सप्लाई

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में इन दिनों भारी तनाव और युद्ध जैसा माहौल है। इस्राइल और अन्य देशों के बीच चल रहे इस बड़े संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसी बीच, भारत सरकार ने सोमवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता की। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को यह बताना था कि बाहर चल रहे इस युद्ध का भारत की जरूरी चीजों पर क्या असर पड़ रहा है। खाद, गैस और तेल के साथ-साथ मंत्रालय ने कई मुद्दों पर जानकारी दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे पास किसानों के लिए खाद का भरपूर भंडार है, रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है और हमारे जो भी नागरिक या नाविक बाहर फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। अलग-अलग मंत्रालयों ने मिलकर काम करते हुए यह पक्का किया है कि देश के अंदर किसी भी जरूरी सामान की सप्लाई चेन न टूटे। अफवाहों और डर के कारण कुछ लोग

जरूरत से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, जिस पर सरकार ने रोक लगाने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

क्या देश में किसानों के लिए खाद की कमी है?

उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने बताया कि देश में खाद यानी फर्टिलाइजर का भंडार बहुत मजबूत है। खरीफ की फसल के लिए जितनी खाद चाहिए, उससे कहीं ज्यादा हमारे गोदामों में भरी हुई है। उदाहरण के लिए, जहां 18.17 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी, वहीं हमारे पास 71.58 लाख मीट्रिक टन मौजूद है। इसी तरह डीएपी खाद भी जरूरत से कई गुना ज्यादा है। सबसे अच्छी बात यह है कि संकट के बाद भी यूरिया के एक बैग (45 किलो) की कीमत 266.5 रुपये और डीएपी की कीमत 1350 रुपये ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, 100% भारतीय निर्यात टैक्स-फ्री

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में सोमवार को एक नए युग की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापार, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाला है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष टॉड मैक्ले की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण समझौते को आधिकारिक रूप दिया गया। यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत मानी जा रही है। इस एफटीए की सबसे खास बात इसकी गति रही है। 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई बातचीत को रिकॉर्ड नौ महीनों के भीतर संपन्न कर लिया गया। इस समझौते के लागू होने से भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। इसके परिणामस्वरूप, न्यूजीलैंड को होने वाले शत-प्रतिशत भारतीय निर्यात पर अब कोई टैरिफ (सीमा शुल्क) नहीं लगेगा। वर्तमान में न्यूजीलैंड द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 उत्पादों पर 10 प्रतिशत

का शुल्क लगाया जाता था। नए समझौते के तहत यह शुल्क खत्म हो जाएगा, जिससे भारतीय कपड़ा और परिधान, चमड़ा उद्योग, टोपी, चीनी मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक्स), कालीन, और वाहन तथा उनके पुर्जों के निर्यात को भारी बढ़ावा मिलेगा। इसके एवज में, भारत ने भी न्यूजीलैंड से आने वाले 95 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दी है या उसे कम कर दिया है। व्यापार सुगमता के साथ-साथ इस एफटीए का एक प्रमुख स्तंभ विदेशी निवेश है। समझौते के तहत, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का भारी-भरकम निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) द्वारा भारत के साथ किए गए समझौते में प्रस्तावित 100 अरब डॉलर के निवेश ढांचे की तर्ज पर ही है। वहीं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के तहत, भारत ने अपने संवेदनशील घरेलू कृषि और डेयरी सेक्टर को इस एफटीए के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है। दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पादों के साथ-साथ अन्य कृषि उत्पादों पर आयात छूट नहीं दी गई है, जिससे भारतीय किसानों और स्थानीय डेयरी उद्योग के हितों की रक्षा सुनिश्चित हुई है। छात्रों को राहतः न्यूजीलैंड ने वैश्विक स्तर पर पहली बार किसी देश के साथ छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा (पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा) से जुड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकेंगे और उन्हें एक्सटेंडेड पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा का लाभ मिलेगा।कुशल पेशेवरों को अवसरः उच्च वेतन वाले रोजगार चाहने वाले स्किल-युक्त भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा का विशेष कोटा निर्धारित किया गया है। इसके जरिए पेशेवर तीन साल तक न्यूजीलैंड में रहकर नौकरी कर सकेंगे।

दिल्ली में हीटवेव को लेकर LG सख्त, अधिकारियों से बोले- एक हफ्ते में जमीन पर दिखना चाहिए असर

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर ठोस कदम जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। राजधानी में तेज होती गर्मी और हीट एक्शन प्लान 2026 का जमीन पर पालन नहीं होता देख एलजी ने संज्ञान लिया है। प्लान में शामिल तैयारियों पर प्रशासन ने अब तक शायद अमल नहीं किया है। हीट वेब से सबसे ज्यादा तकलीफ बाहर काम करने वाले मजदूरों को हो रही है। बेसहारा पशु पक्षी भी तकलीफ में हैं। इनकी राहत के लिए जमीन पर कोई कार्यवाही अब तक नजर नहीं आ रही है। सोमवार को हीटवेव को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा की गई और साफ निर्देश दिए गए कि हीट एक्शन प्लान को एक हफ्ते के भीतर प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू किया जाए। उपराज्यपाल ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट इस पूरे अभियान में अहम भूमिका निभाएं और अपने-अपने क्षेत्रों में समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। सार्वजनिक स्थानों पर गर्मी से राहत देने के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि हीटवेव से निपटने के लिए सभी विभाग आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा और जागरूकता जैसे उपायों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल ने सिर्फ लोगों ही नहीं, बल्कि शहर के पशु-पक्षियों के लिए भी विशेष इंतजाम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में इनके लिए पानी और राहत की व्यवस्था करना भी जरूरी है। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएं। सरकार इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी करेगी, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दिल्ली में हीटवेव से निपटने के लिए उपराज्यपाल ने निगरानी अपने पास रखी है, जिस कारण आने वाले दिनों में इसका असर जमीन पर दिखने की उम्मीद है।

जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में अब पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, बोले- न्याय मिलने की उम्मीद टूटी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्माको एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने अपने पत्र में न्याय मिलने की उम्मीद टूटने की बात कहते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, 'मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है। इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए फैसला किया है। जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखूंगा।'दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की मांग को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने इस मामले की सुनवाई कर रहीं जज स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात

का आरोप लगाते हुए मामले को किसी दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी भी की और याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में पेश ही नहीं होने का एलान कर दिया है।अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, 'मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। हमें कई महीने जेल में रखा लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। कोर्ट ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले के हाई कोर्ट में चुनौती दी ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने लगा। तब मेरे मन में सवाल उठा कि क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है?'वहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र आज न्यायाधीश के समुख लिखने का प्रयास किया है हम उसकी निंदा करते हैं। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

ममता बनर्जी ने किया जीत का दावा; बोलीं- मां माटी मानुष की लहर, अब सिर्फ वक्त का इंतजार

प.बंगाल।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मां, माटी, मानुष की जीत अब भविष्यवाणी नहीं, बल्कि सिर्फ समय की बात है।उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित पदयात्राओं और जनसभाओं में आम लोगों का जबरदस्त उत्साह, स्नेह और भावनात्मक समर्थन देखकर वह बेहद प्रभावित हुई हैं। उन्होंने लिखा कि यह रिश्ता वर्षों से हर चुनौती के समय जनता के साथ खड़े रहने से बना है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सदियों से सौहार्द, संस्कृति और सभ्यतागत गौरव का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र धरती पर उन विभाजनकारी और विनाशकारी ताकतों के लिए जगह नहीं , जो बंगाल को उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहती हैं। ऐसी ताकतें बंगाल की विरासत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता की लालसा में जनता के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को बंगाल की जागरूक और एकजुट जनता लोकतांत्रिक जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार के विकास कार्य राज्य के हर कोने तक पहुंचे हैं और कोई भी दुर्भावनापूर्ण ताकत इस रफ्तार को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जनता केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं बंगाल के लोगों की सुरक्षा कवच हैं और दुनिया की कोई ताकत इन्हें छीन नहीं सकती।ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्य की जनता हमेशा की तरह विकास, शांति और प्रगति के पक्ष में खड़ी रहेगी। दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की कि भाषा, संस्कृति और बंगाल की गौरवशाली विरासत की रक्षा के लिए 29 अप्रैल को जोराफूल चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं और मां, माटी, मानुष उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं।

'पढ़ाई, लिखाई और दवाई हमारी प्राथमिकता' : पीएम मोदी

बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। आज प्रचार का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का प्रचार करने बैरकपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा, '1857 में इसी बैरकपुर की धरती ने आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी थी। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है।' भाजपा के चुनावी नारे और बंगाल में बदलाव की बयार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने रैली में कहा कि बंगाल में हर ओर एक ही नारा सुनाई दे रहा है 'पलटनो दरकार, चाई बीजेपी सरकार।' यानी जनता बदलाव चाहती है और भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है।रैली को चुनाव प्रचार की अंतिम सभा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरे राज्य में लोगों का मूड देखकर उन्हें विश्वास है कि 4 मई को नतीजे आने के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने फिर बंगाल आएंगे।

'जनता ही मेरा परिवार है और उनके बीच रहकर सुकून मिलता है'

उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मिले जनसमर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि रैलियों और रोड शो के दौरान लोगों द्वारा दिए गए संदेश, पत्र और चित्र उनके लिए बेहद खास हैं। वह रात में समय निकालकर इन भावनाओं को समझते हैं और लोगों के संदेशों को पढ़ते हैं। अपने लंबे राजनीतिक सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पिछले कई दशकों से देशभर में लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी द्वारा सौंपी गई हर जिम्मेदारी को निभाते आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ही उनका परिवार है और उनके बीच रहकर उन्हें सुकून मिलता है।पीएम मोदी ने दावा किया कि राज्य में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती से उनका जुड़ाव बेहद खास है और यहां के अनुभवों को वह अपने जीवन का आशीर्वाद मानते हैं। उनके अनुसार, जिस तरह जनता बड़ी संख्या में सामने आ रही है, उससे स्पष्ट है कि बैरकपुर समेत पूरा बंगाल बदलाव के लिए तैयार खड़ा है।पीएम मोदी ने अपने चुनावी रोड शो और रैलियों को 'तीर्थ यात्रा' जैसा अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और लगातार कार्यक्रमों के बावजूद उन्हें थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि लोगों का उत्साह उन्हें लगातार ऊर्जा देता रहा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दूर-दूर तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जिसे देखकर वह फिर से पूरे जोश के साथ उनके बीच पहुंच जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि मां काली के भक्तों के बीच जाने से उन्हें विशेष ऊर्जा मिलती रही।

बैरकपुर से पीएम मोदी की 5 बड़ी गारंटी

पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के लिए पांच अहम गारंटियों का एलान किया। उन्होंने कहा कि ये वादे बंगाल के विकास और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पीएम मोदी की पहली गारंटी के तहत रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले लोगों को बैंक के जरिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उनका कारोबार मजबूत हो सके। दूसरी गारंटी में उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी भर्तियां तय समयसीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएंगी। तीसरी गारंटी में रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। वहीं चौथी गारंटी के तहत राज्य में सातवें वेतन आयोग को तुरंत लागू करने का वादा किया गया। पांचवीं और अहम गारंटी में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य से पलायन रोकने के लिए गांवों में 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिल सके।

ऊश्ण के पास न तो विजन है और न ही कुछ करने की नीयत

इस दौरान प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस (ऊश्ण) पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के पास बंगाल के विकास के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है। पार्टी ने अपने 15 साल के शासन का कोई ठोस हिसाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि न तो उनके पास विजन है और न ही कुछ करने की नीयत। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी के शासन में सिंडिकेट राज और अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं, जिन्हें खत्म करना जरूरी है।

कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना भी की

रैली से पहले पीएम मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक थंथानिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां काली का आशीर्वाद भी लिया। यह मंदिर 300 साल से अधिक पुराना और श्रद्धालुओं के बीच बेहद आस्था का केंद्र माना जाता है। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार कौस्तव बागची, तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक राज (राजू) चक्रवर्ती और सीपीआई(एम) के सुमन रंजन बंद्योपाध्याय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बैरकपुर विधानसभा सीट उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है और यहां दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

सम्पादकीय

अंधश्रद्धा को सही चुनौती!

अपने चमत्कार दिखाकर धार्मिक श्रद्धा के बाजार और भक्ति के व्यापार में बहुत जल्द तरक्की करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है। महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एएनआईएस) ने दो परीक्षणों के जरिए मध्यप्रदेश के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्चमत्कारीश् दावों को चुनौती दी है। एएनआईएस के संस्थापक प्रो. श्याम मानव ने बीते दिनों नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को दो विशेष परीक्षणों से गुजरना होगा। अगर वे इन परीक्षणों में सफल होते हैं तो उन्हें रुपए 80 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी, लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो उनके कार्यक्रम शुल्क से जमा 8 लाख जब्त कर लिए जाएंगे। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है, हालांकि उनका कहना है कि श्मेरे पास कोई अलौकिक शक्तिनहीं है, सभी शक्तियां बजरंगबली की हैं। मुझे केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं धर्मांतरण का विरोध करता हूं। इस पर प्रो. श्याम मानव का कहना है कि श्अगर वे वाकई दिव्य शक्तियां रखते हैं, तो हमारे परीक्षण में क्या डर? हम सार्वजनिक रूप से सिद्ध करने को तैयार हैं। गौरतलब है कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने यह चुनौती तीन शर्तों के साथ रखी है, धीरेंद्र शास्त्री को बंद लिफाफों में रखे 10 अलग-अलग व्यक्तियों के नाम, उनके माता-पिता के नाम, उम्र और मोबाइल नंबर सही-सही पहचानना होगा। धीरेंद्र शास्त्री को परीक्षण वाली जगह पर बगल के कमरे में रखी 10 अलग-अलग वस्तुओं की पहचान बिना देखे करनी होगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग नागपुर में होगी और दोनों पक्षों की पांच-पांच सदस्यीय समिति इसकी निगरानी करेगी। बजरंगबली की शक्ति पर अटूट आस्था दिखाने वाले शास्त्री इन चुनौतियों को मानेंगे या नहीं, उसमें कामयाब होंगे या नहीं, यह तो बाद की बात है। लेकिन इस समय समाज जिस तेजी से अंधश्रद्धा का शिकार हो रहा है, आस्था और अंधविश्वास में फर्क को मिटाया जा रहा है, धर्म के मायने बदलकर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत, बदला लेने की भावना को बढ़ावा मिल रहा है, संविधान को अपमानित कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, उसमें यह बेहद जरूरी है कि इस तरह के क्रियाकलापों पर तार्किक सवाल उठाए जाएं। प्रो. श्याम मानव ने इस चुनौती के साथ एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में अंधविश्वास बढ़ा है। हालांकि इस आरोप का दायरा बढ़ाकर पूरे देश पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि शायद ही कोई राज्य, कोई जिला ऐसा होगा जहां अंधविश्वास से ग्रस्त जनता और उसे बढ़ावा देने वाला शक्तिशाली, संपन्न तबका मौजूद न हो। इसके बरक्स वैज्ञानिक सोच और नजरिए को बढ़ावा देने वाले लोग नगण्य रह गए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने पिछले सोमवार ही अपने परिवार के साथ छतरपुर के बागेश्वर धाम में बालाजी की पूजा की और पीठाधिश्वर धीरेंद्र शास्त्री से भी मुलाकात की। जिसके बाद बी आर गवई ने कहा कि बागेश्वर धाम में सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहें, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बागेश्वर धाम में संचालित कैंसर हॉस्पिटल का भी जिक्र किया और वहां की स्वास्थ्य सेवाएं भी देखीं। व्यक्तिगत तौर पर श्री गवई चाहे किसी भी धर्मालय में जाएं और जो चाहें पूजा करें। लेकिन जिस पद पर वे रह चुके हैं, उसके बाद इस तरह किसी विशेष धाम के बारे में बयान देना उचित नहीं है। अच्छी बात है कि छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर अस्पताल बनवाया है, लेकिन बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी सरकार की है, क्या उस पर भी श्री गवई कहेंगे। वैसे जब मुख्य न्यायाधीश रहते हुए डी. वाय. चंद्रचूड़ के साथ प्रधानमंत्री ने उनके घर पर गणेश पूजा में हिस्सा लिया। या अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश का संबोधन दिया, उसके बाद न्यायपालिका से बची हुई आस भी टूटने लगी है। ध्यान रहे कि इन्हीं जस्टिस गवई के ऊपर एक वकील ने अदालत के भीतर जूता उछाल दिया था, क्योंकि विष्णु की खंडित प्रतिमा को लेकर दिए उनके बयान पर वकील को सनातन का अपमान महसूस हुआ था। अब वही बी आर गवई धीरेन्द्र शास्त्री के कामों को सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। तो क्या देश में बड़ी चालाकी से माहौल तैयार हो रहा है कि कु छ समय बाद हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा हो जाए तब विरोध करने वाला कोई बचे ही नहीं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री इस पूरे खेल में एक नया और युवा किरदार ही हैं। उनसे पहले आसाराम, नित्यानंद, अशोक खरात और न जाने कितने तरह के किरदारों ने अंधश्रद्धा को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति, खेल, कला और फिल्म जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियां इनके यहां माथा नवाते दिखती हैं, तो समाज का पीड़ित, कमजोर तबका सोचता है कि हम भी ऐसा ही करें तो शायद हमारी तकलीफें दूर हो जाएं, हमें भी ठाठ से रहने के मौके मिले। इस तरह जनता को आराम पहुंचाने की जो जिम्मेदारी सरकार की है, वो अंधश्रद्धा के जिम्मे आ जाती है, जो कभी भी दान की चादर में मिले अरबों रुपए बटोर कर उठा ली जाती है। जनता को न आराम मिलता है, न ठाठ! ऐसे खेल को रोकने के लिए जरूरी है कि प्रो. श्याम मानव ने जो चुनौती पेश की है, उसे व्यापक स्थान मिले।

ट्रंप ने कहा भारत को नरक मगर मोदी को चुनाव से फुरसत नहीं!

शकील अख्तर

कभी कांग्रेस का केन्द्र सहित सभी राज्यों में राज था। कांग्रेसी कोई छोटा मोटा संस्थान भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्दिरा गांधी से कहा गया कि यह जेएनयू का छात्रसंघ हमारे पास नहीं है। इन्दिराजी ने जवाब दिया कि कुछ विपक्ष के लिए भी छोड़ना चाहिए। कमलापति त्रिपाठी ने बनारस में अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण को चुनाव खर्चे के लिए पैसे दिए। 1980 के लोकसभा चुनाव की बात है। कई उदाहरण हैं और इनकी शुरुआत खुद नेहरू से होती है। नेहरू के सबसे बड़े आलोचक लोहिया जो एक तरफ कहते थे कि अगर मुझे कु छ हो गया तो मेरी सबसे अच्छी देखभाल नेहरू के घर पर होगी और दूसरी तरफ वे नेहरू पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाते थे। ऐसे हवा हवाई आरोप जैसे आजकल प्रधानमंत्री मोदी लगाते हैं कि कांग्रेस के पास बोरों में भर-भर कर पैसा जाता है, 50 करोड़ की गर्ल फ्रेंड! ऐसे ही उन दिनों 25 हजार रुपए खर्च होते थे। तो लोहिया ने आरोप लगाया कि नेहरू का व्यक्तिगत खर्च 25 हजार रुपए रोज है। और नेहरू ने इतने ही रुपए 25 हजार लोहिया के चुनाव खर्चे के लिए पहुंचाए। साथ में एक जीप और लोहिया चुनाव किस के खिलाफ लड़ रहे थे? खुद नेहरू के। 1962 का लोकसभा चुनाव। फूलपुर से। नेहरू को जीतना ही था। लेकिन उन्होंने कहा कि लोहिया को लोकसभा में होना चाहिए। ऐसा ही वाजपेयी के लिए भी कहते थे। नेहरू से लेकर इन्दिरा, राजीव गांधी तक सब विपक्ष के नेता और विपक्ष की जगह का महत्व जानते थे और उसे बनाए रखने में मदद करते थे। नेहरू ने 1962 की लोहिया की हार के बाद 1963 में उनको फर्रुखाबाद के उपचुनाव में जिताने में मदद भी की थी। राजीव गांधी का ज़िक्र किया तो यह इतनी बड़ी बात खुद राजीव ने कभी नहीं बताई वाजपेयी ने ही बताई थी कि जब राजीव गांधी को उनके हार्ट की गंभीर समस्या का मालूम पड़ा तो उन्हें प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाकर अमेरिका भेजा और वहां इलाज की सारी व्यवस्था की। राजीव की हत्या के बाद वाजपेयी ने जब यह बात बताई तो सबको मालूम पड़ा। मगर आज क्या हो रहा है? मोदी अमित शाह हर चुनाव जीतना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर। बंगाल में सारी ताकत लगा दी है। चुनाव आयोग मीडिया बाकी संस्थाएं सब साथ हैं। बड़ी तादाद में केन्द्रीय सुरक्षा बल लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो हफ्ते से बंगाल में डेरा जमाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि अभी 27 अप्रैल सोमवार जब दूसरे दौर के चुनाव प्रचार खत्म नहीं हो जाता वे वहीं रहेंगे। इससे पहले कभी किसी राज्य के चुनाव में गृहमंत्री सारे काम छोड़कर एक राज्य में रहे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बाकी सब काम और समस्याएं तो एक तरफ हैं। मगर सीमवर्ती राज्य मणिपुर में तो बुरी तरह हिंसा की आग धधक रही है। मगर न प्रधानमंत्री न गृह मंत्री किसी को मणिपुर की चिंता है। और बंगाल में केन्द्रीय सुरक्षा बल कितने हैं? करीब ढाई लाख से ज्यादा जवान। बंगाल पुलिस को एकदम किनारे कर दिया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह एक वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं ए बंगाल पुलिस हट जाओ! कल को कोई नेता किसी दूसरे राज्य की पुलिस के लिए भी ऐसा ही कहेगा। और कोई राज्य का नेता केन्द्रीय सुरक्षा बल से भी कह सकता है। कैसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं देश के

गृहमंत्री? और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वह राज्य की पुलिस के अपमान, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री के बार-बार टीएमसी के गुंडे कहने से लेकर दीदी के गुंडे कहने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा लेकिन बाइक पर आने जाने पर रोक लगा रहा है। देश में खासतौर से गांवों में आने-जाने का सबसे मुख्य साधन क्या है? दोपहिया वाहन। उनके चलाने पर रोक लगा दी। मगर जब ज्यादा विरोध हुआ तो पीछे किसी को बिठाने पर रोक लगा दी। गांव का बाइक का हिसाब-किताब समझते हैं ये? एक आदमी बाइक पर जाता है तो महंगा पड़ता है। दो में किफायती और तीन में सस्ता। इस तरह हिसाब-किताब लगाकर गांव कस्बों में लोग अपना काम चलाते हैं। बड़े शहरों में सरकार कहती है गाड़ी पूल करो। मगर कोई नहीं मानता। लेकिन गांव, कस्बों में बिना किसी के कहे अपने आर्थिक हालात को देखकर लोग बाइक पूल करते हैं। पता नहीं कितना तो सामान इस पर आता-जाता है। मगर चुनाव आयोग कुछ नहीं देख रहा। पोलिंग के 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद होती हैं। मगर बंगाल में 96 घंटे की शराबबंदी कर दी गई है। मतलब वह सब काम किए जा रहे हैं जो कभी नहीं हुए। हर हाल में चुनाव जीतना है। जिताना है। लेकिन क्या यह जिद, सत्ता की भूख बंगाल तक ही है? अभी तो कई राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का कोई अता पता नहीं है! जैसे बंगाल के मिजाज से भाजपा का मेल नहीं खाता है। वैसे ही इन पांच राज्यों में जहां बंगाल के साथ चुनाव हो रहे हैं केरल और तमिलनाडु में भी भाजपा कहीं नहीं है। क्या अब ऐसा ही हर हाल में चुनाव जीतो अभियान उन सब जगह होगा जहां बीजेपी नहीं है? ऐसे सारे राज्य सीमावर्ती हैं। लेकिन स्थिति की इस नजाकत को क्या बीजेपी समझती है? अब तो यह साफ हो गया है कि बीजेपी को चुनाव जीतने के अलावा और कोई काम नहीं है। और बीजेपी नहीं बीजेपी की केन्द्रीय सरकार को। देश की विदेश की किसी बात से कोई मतलब नहीं। पहले मणिपुर के लोग कहते थे कि क्या हम देश में नहीं हैं? प्रधानमंत्री को हमारी चिंता ही नहीं! मगर अब तो खुद प्रधानमंत्री के लिए विदेश से क्या-क्या कहा जा रहा है उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उनके लिए क्या अब तो ट्रंप देश के लिए भी कहने लगा। नरक! जिसे महाकवि इकबाल ने कहा था- सारे जहां से अच्छा! लेकिन इन्हें तो इकबाल के नाम से भी प्राब्लम है तो जिन स्कूलों में गाया जाता था वहां बंद करवा दिया। और कुछ टीचरों के खिलाफ तो इसके लिए मुकदमे तक करवा दिए।

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा लिखने वाले का विरोध और भारत को नर्क कहने वाले ट्रंप का ऐसा सम्मान की उसकी जीत के लिए हवन करवाए गए और खुद प्रधानमंत्री मोदी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने लगे। लेकिन हमें नरक कहा तो चलो एक बार बर्दाश्त कर लेते मगर वे तो उससे भी आगे जाकर हमारे जख्मों पर और नमक छिड़क रहे हैं!

जिस पाकिस्तान को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। उसे अब ट्रंप महान देश कहकर पुकार रहा है। भारत के लिए इससे बड़ी तकलीफ की बात कोई और नहीं हो सकती। उसकी आतंकवादी गतिविधियों को दुनिया के सामने रखकर मनमोहन सिंह सरकार और उससे पहले कांग्रेस की ही नरसिंहा राव सरकार ने उसे फेल स्टेट, असफल देश के रूप में स्थापित कर दिया था। मगर अब वह अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवा रहा है। ट्रंप वहां के प्रधानमंत्री के साथ वहां के उस आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे हैं जो पहलगाम की आतंकवादी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सही में प्रधानमंत्री मोदी को कोई मतलब नहीं। बस बंगाल चुनाव जीतना है। क्या हो जाएगा बंगाल जीतकर? और बंगाल ही क्या जो राज्य अभी तक नहीं जीते पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र, तेलंगाना और केरल एवं तमिलनाडु का जिक्र तो ऊपर किया वे सब भी जीत जाएं और विदेशों में ऐसी ही बेइज्जती होती रहे तो ऐसे पूरे भारत पर कब्जे का क्या मतलब? जैसा शुरू में लिखा कांग्रेस जीतती थी तो दुनिया में देश का सम्मान करवाती थी। भारत की कीमत पर अपना राजनीतिक लाभ कभी नहीं देखती थी। लेकिन आज सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव! चुनाव जीतने के अलावा किसी और बात से कोई मतलब नहीं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के नतीजे असल में क्या संकेत देते हैं?

टी एन अशोक

ज्यादातर लोकतंत्रों में भारी मतदान को एक अच्छी बात माना जाता है, जो चुनाव प्रणाली में भरोसे की निशानी है। परन्तु भारत में यह बात इतनी सीधी नहीं है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में जो जबरदस्त भागीदारी देखने को मिलीकृजहां मतदान क्रमशरू 84 प्रतिशत और 92 प्रतिशत के पार पहुंच गईकृउसे और गहराई से समझने की जरूरत है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये संकेत हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, और कुछ मामलों में, जान-बूझकर की गई राजनीतिक चालें हैं। पहली नजर में, तमिलनाडु की रिकॉर्ड मतदान एक जानी-पहचानी कहानी जैसी लगती है। इतिहास गवाह है कि जब-जब मतदान में अचानक उछाल आया हैकृखासकर 2011 मेंकृतब-तब सत्ता-विरोधी लहर भी जोरों पर रही है। इससे अपने-आप यह सवाल उठता हैरू क्या सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्रकडगम (द्रमुक) मुश्किल में है? इसका जवाब है, जरूरी नहीं। 2026 में मतदान में जो उछाल आया है, वह एक काफी बदले हुए मतदाता सूची पर आधारित है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वजह से मतदाताओं की संख्या लाखों में कम हो गई थी। इसलिए, भले ही मतदान का प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन मतदाताओं की कुल संख्या में जो बढ़ोतरी हुई हैकृपिछले चुनावों के मुकाबले लगभग 19 लाखकृवह उतनी बड़ी नहीं है जितनी दिखती है। दूसरे शब्दों में, यह मतदाताओं का एक छोटा समूह है जो ज्यादा जोश से मत डाल रहा है, न कि कोई पूरी तरह से नई लहर जो चुनावी मैदान का नक्शा बदल रही हो। यह फर्क समझना जरूरी है। यह इस सोच को थोड़ा नरम करता है कि सत्ता के खिलाफ कोई बहुत बड़ी लहर चल रही है। अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी, तमिलगावेट्रीकडगम (टीवीके) के चुनावी मैदान में उतरने से युवा मतदाताओं में, खासकर 18 से 40 साल के लोगों में, यकीनन नया जोश भर गया है। मतदाताओं का यह समूहकृजो तमिलनाडु में पहले से ही काफी बड़ा हैकृइस बार बड़ी संख्या में मत डालने के लिए बाहर निकला है। लेकिन जोश होना और चुनावी तौर पर एकजुट होना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। विजय की लोकप्रियता फैली हुई है, शहरी इलाकों में ज्यादा है, और अभी भी अपने राजनीतिक सफ्रर के शुरुआती दौर में है। उनकी मौजूदगी से शायद ये हुआ हैरू मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, खासकर पहली बार मत डालने वालों के बीच। द्रमुक-विरोधी मत एक जगह जमा होने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में बंट गए हैं। खासकर शहरी इलाकों की करीबी चुनावी लड़ाइयों में, जिससे नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। द्रमुक के लिए, यह विरोधाभासी रूप से फायदेमंद है। एक बंटा हुआ विपक्ष, सत्ता-विरोधी लहर के पूरी तरह हावी होने के जोखिम को कम कर देता है। शोर-शराबे के बावजूद, द्रमुक के पास कई ऐसे फायदे हैं जो खामोश हैं, महिला मतदाता, जिनकी संख्या अब पुरुषों से ज्यादा है, लगातार कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता के पक्ष में रही हैं। शासन का एक अपेक्षाकृत स्थिर माहौल, जिसमें कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। गहरे संगठनात्मक नेटवर्क, जिनकी बराबरी नए आए दल नहीं कर सकते। नेता एम. के. स्टालिन ने भड़काऊ बयानबाजी से परहेज किया है, और द्रमुक को गुस्से का निशाना बनने के बजाय स्थिरता के रक्षक के रूप में पेश किया है। इस संदर्भ में, भारी मतदान, शायद प्रतिस्पर्धी लामबंदी को दर्शाता है, न कि किसी अस्वीकृति को। विपक्ष का खेमा एकजुट होने के बजाय ज्यादा भीड़भाड़ वाला है। जयललिता के बाद पैदा हुए नेतृत्व के खालीपन के चलते, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रकडगम (अन्नाद्रमुक) अभी भी नेतृत्व की स्पष्टता के लिए संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना विस्तार तो किया है, लेकिन द्रविड़ राजनीतिक परिवेश में उसकी संरचनात्मक सीमाएं अभी भी बनी हुई हैं। उनके गठबंधन का गणित तो शायद काम कर जाए, लेकिन उनकी कहानी में कोई तालमेल नहीं है। याद रहे भारी मतदान वाले चुनावों में, अक्सर गणित से ज्यादा कहानी मायने रखती है। अगर तमिलनाडु में मतदान का रुझान अस्पष्ट है, तो पश्चिम बंगाल में यह बेहद स्पष्ट है। 92 प्रतिशत का आंकड़ा पार करना, न केवल लोगों की भागीदारी को दर्शाता है, बल्कि उनके जोश को भी दिखाता हैकृएक ऐसा समाज जो गहरे तौर पर ध्रुवीकृत है और मतदान को अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। यहां, मतदान का मकसद जिज्ञासा कम और मजबूरी ज्यादा है। मत डालने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के वापस लौटने की खबरें काफी अहम हैं।

बंगाल में लंबे समय से प्रवासन के कारण चुनावी भागीदारी कमजोर होती रही है। उनका वापस लौटना यह संकेत देता हैरू एक ऐसी सोच कि यह चुनाव सामान्य से कहीं ज्यादा मायने रखता है। राजनीतिक दांव-पेंच को लेकर एक बढ़ा हुआ एहसास, जो अब उनकी निजी पहचान से भी जुड़ गया है। यह कोई सामान्य चुनावी लामबंदी नहीं है। यह भावनाओं की पुकार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस चुनाव को श्शासन बनाम विपक्षश् की लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि बंगाल बनाम बाहरी दखल की लड़ाई के तौर पर पेश किया है। नागरिकता कानून (सीएए), संभावित समान नागरिक संहिता

(यूसीसी), और मतदाता सूची में संशोधन (एसआईआर) से जुड़े आरोपों जैसे मुद्दों को, सांस्कृतिक और राजनीतिक खतरे की एक बड़ी कहानी में पिरो दिया गया है। कोई इस नजरिए से सहमत हो या न हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह काफी असरदार साबित हुआ है। यहां भारी मतदान शायद इन बातों को दर्शाता है, अल्पसंख्यक और ग्रामीण मतदाताओं का एकजुट होना। भाजपा के कथित वैचारिक विस्तार के खिलाफ एक जवाबी लामबंदी। मत को किसी आकांक्षा के बजाय, अपनी सुरक्षा के एक हथियार के तौर पर देखना। सबसे अहम सवाल यह हैरू क्या 92प्रतिशत से अधिक का मतदान मौजूदा सत्ताधारी दल के प्रति गुस्से का संकेत है, या फिर चुनौती देने वाले दल के प्रति डर का? बंगाल में, सुबूत बाद वाली बात की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)ने अपनी कमजोरी को एक जरूरी मुद्दे में बदल दिया है। सिर्फ अपने काम के बचाव के बजाय, उसने हार के नतीजों को ही नए सिरे से परिभाषित कर दिया है।

भाजपा के लिए, इससे एक अजीब विरोधाभास पैदा हो गया है। उसके उभार ने मुकाबले का दायरा तो बढ़ाया हैकृलेकिन साथ ही एक ऐसी प्रतिक्रिया भी पैदा कर दी है, जिससे उसके विरोधियों के बीच मत डालने वालों की संख्या बढ़ गई है। अगर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को साथ-साथ देखें, तो वे एक ही घटना के बारे में दो अलग-अलग कहानियां बताते हैं। तमिलनाडु में भारी मतदान प्रतिस्पर्धा, युवाओं का भारी संख्या में प्रवेश और बिखरे हुए विपक्ष की वजह से हुआ। पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण, पहचान और अस्तित्व के लिए माने जाने वाले दांव की वजह से। एक में, यह बढ़त मौजूदा सरकार को स्थिर कर सकती है। दूसरे में, यह उसे बचा सकती है। भारी मतदान अपने आप में कोई फैसला नहीं है। यह एक सवाल है। तमिलनाडु में, यह पूछता है कि क्या कोई नई राजनीतिक ताकत जोश को सत्ता में बदल सकती हैकृया सिर्फ मतों को फिर से बांट सकती है? पश्चिम बंगाल में, यह पूछता है कि क्या डर को वफादारी में बदला जा सकता हैकृऔर क्या ध्रुवीकरण ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं हो सकती? किसी भी तरह से देखें, भारी मतदान की संख्या जितना दिखाती हैं, उतना ही छिपाती भी हैं। भारतीय चुनावों में, अक्सर भारी मतदान के पीछे जो होता है, वही तय करता है कि आखिर में कौन राज करेगा।

देश में संसद की पवित्रता की बहस

अजीत द्विवेदी

भारत में किसी भी चीज को नष्ट करने के कई तरीकों में से एक तरीका यह है कि उसे पवित्र बना दिया जाए। उसे पूजा के योग्य बना दिया जाए। जैसे ही हमारे यहां कहा जाए कि अमुक चीज तो पवित्र है और हम उसकी पूजा करते हैं तो समझ लें कि वह चीज ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। उसका नष्ट होना अवश्यम्भावी है। मिसाल के तौर पर भारत में नदियों की स्थिति देखी जा सकती है। नदियों को भारत में माता का दर्जा दिया जाता है और पूजा की जाती है लेकिन पूजा करने वाला व्यक्ति भी नदी की सफाई और उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखता है। सारा कचरा नदियों में जाता है, लोगों के घरों के गंदे नाले नदियों में जाते हैं, औद्योगिक इकाइयों का कचरा नदियों में गिरता है, इसके अलावा और क्या क्या होता यह लिखने की जरूरत नहीं है। सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं और किसी भी नदी की सफाई नहीं हो पाती है। इसी के हमलोगों ने पहाड़ों को पूजना शुरू किया और अपने लालच में उनकी ऐसी खुदाई शुरू की या पहाड़ काट कर ऐसे निर्माण शुरू किए कि हर पर्वत श्रृंखला अस्तित्व का संकट झेल रहा है। इसी तरह भारत में पेड़ों की पूजा होती है और फिर ऐसी अंधाधुंध कटाई होती है कि लाखों, करोड़ों हेक्टेयर में फैले जंगल समाप्त हो गए। हम अपनी देवियों की पूजा करते हैं और हमारे घरों में स्त्रियों की क्या स्थिति है यह राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं। ऐसी अनेक मिसालें और भी दी जा सकती हैं। लेकिन विषय को समझने के लिए इतना पर्याप्त है।इतनी लंबी भूमिका की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस समय देश में संसद की पवित्रता की बहस चल रही है। बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस बात से आहत हैं कि राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर समोसे खा रहे थे और चाय पी रहे थे। असल में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने लोकसभा से निलंबित सांसदों के साथ मकर द्वार के पास बैठ कर समोसे खाए थे और चाय पी थी। इसे लेकर भाजपा के सांसदों ने नाराजगी जताई तो देश के दो सौ से ज्यादा कथित गणमान्य लोगों ने चिट्ठी लिखकर भी भी खबर आई, जिसमें राहुल गांधी के व्यवहार को संसद की गरिमा के विरुद्ध बताया गया और उनकी आलोचना की गई। इससे पहले भाजपा के सांसदों ने तृणमूल के एक बुजुर्ग सांसद की शिकायत स्पीकर से की थी, जिसमें कहा गया है कि वे संसद परिसर में सिगरेट पी रहे थे। संसद के अंदर ई सिगरेट पीने की शिकायत भी की गई। ऐसे ही कांग्रेस की एक सांसद कुत्ता लेकर संसद परिसर में आ गई थीं तो उसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी।इसमें से ज्यादातर घटनाएं सामान्य मानवीय व्यवहार से जुड़ी हैं। हो सकता है कि किसी सांसद के सामान्य मानवीय व्यवहार से कोई दूसरा सदस्य आहत हो जाए। जैसे फिल्म अभिनेत्री से सांसद बनीं भाजपा की एक नेता को राहुल गांधी का व्यवहार 'टपोरी' जैसा लगता है और उनका दावा है कि राहुल गांधी को देख कर महिला सांसद असहज हो जाती हैं।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीएः किसानों, युवाओं, नौकरियों और विकास के लिए महिलाओं के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक समझौता

पीयूष गोयल

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिस पर सोमवार को हस्ताक्षर किये जायेंगे, विकसित दुनिया के साथ भारत की सहभागिता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को किसानों, महिलाओं, युवाओं और रोजगार सृजक उद्योगों के लिए ठोस लाभ में बदलने से जुड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण में हुई निर्णायक प्रगति को प्रतिबिंबित करता है। यह एफटीए प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ शामिल हैं, के साथ हुए कई ऐतिहासिक व्यापार समझौतों के बाद हो रहा है। ये समझौते वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं और निर्यातकों को दुनिया की कुछ सबसे लाभकारी अर्थव्यवस्थाओं में, यहां तक कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितता और उथल-पुथल के बीच भी, प्रतिस्पर्धा आधारित बढ़त प्रदान करते हैं।

निर्यात और रोजगार को मजबूत बढ़ावा

दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी इस समझौते के केंद्र में न्यूजीलैंड की यह प्रतिबद्धता है कि वह तुरंत ही सभी भारतीय उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर देगा, जिससे उस बाजार में एक महत्वपूर्ण बाधा दूर होगी, जहाँ हमारे प्रमुख निर्यात पर वर्तमान में 10त्न शुल्क लगाया जाता है।यह वस्त्र, कालीन, धागे, कपड़े, फुटवियर, बैग, बेल्ट, वाहन घटक, मशीनरी, उपकरण, रत्न और आभूषण तथा हस्तशिल्प जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। रोजगार के अवसरों का सृजन करने वाले ये उद्योग भारत के एमएसएमई इकोसिस्टम की रीढ़ हैं और इन्हें मूल्य प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुँच से लाभ मिलेगा। इससे निर्यात बढ़ेगा और निर्माण केन्द्रों, कारीगर समुदायों और लघु उद्यमों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।यह समझौता उस व्यापक दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जो 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद से भारत की व्यापार नीति का मार्गदर्शन कर रहा है। यह समावेश, सशक्तिकरण और साझा समृद्धि में निहित है। व्यापार को राष्ट्रीय परिवर्तन के उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाता है।

नारी शक्ति

इस समझौते की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला एफटीए है। वार्ता टीम की लगभग सभी सदस्य महिलायें थीं। इनमें मुख्य वार्ताकार, उप मुख्य वार्ताकार, क्षेत्र प्रमुख और न्यूजीलैंड में भारत की राजदूत शामिल हैं।यह उपलब्धि मोदी सरकार में महिलाओं के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। यह शासन, नेतृत्व और विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है और राष्ट्रीय विकास के संचालक के रूप में नारी शक्ति के विचार को सुदृढ़ करती है।

किसान पहले

एफटीए की संरचना कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गयी है। न्यूज़ीलैंड कीवी, सेब और शहद के लिए कृषि उत्पादकता कार्ययोजनाओं का समर्थन करेगा। इन पहलों में बेहतर बीज सामग्री, अनुसंधान सहयोग, किसानों के लिए क्षमता निर्माण, बागवानी प्रबंधन प्रथाएं, कटाई के बाद सुधार, खाद्य सुरक्षा प्रणाली और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना शामिल है। सेब उत्पादकों और सतत मधुमक्खी पालन तौर-तरीकों के लिए परियोजनाएं उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाएंगी, जिससे कृषि समृद्धि में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, भारत ने अपने प्रमुख कृषि हितों की मजबूती से सुरक्षा की है। डेयरी उत्पादों (जैसे दूध, क्रीम, व्हे, दही और पनीर); प्याज, चना, मटर, मकई, बादाम, चीनी और कुछ ख़ास तेल और वसा जैसी संवेदनशील वस्तुओं को शुल्क छूट से बाहर रखा गया है। समझौता सुनिश्चित करता है कि घरेलू किसान हानिकारक आयात प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रहें। किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा करना सभी व्यापार वार्ताओं में भारत के दृष्टिकोण का केंद्र रहा है।

युवा और पेशेवर

समझौते का एक प्रमुख स्तंभ छात्रों और कुशल पेशेवरों के लिए बढ़ी हुई आवागमन की सुविधा है, जो भारत के युवाओं के लिए नए वैश्विक मार्ग का निर्माण करती है।किसी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते में पहली बार, न्यूजीलैंड ने भारतीय छात्रों के आवागमन और अध्ययन के बाद काम करने के अवसरों के लिए एक संरचना-युक्त रूपरेखा पेश की है। भारतीय छात्रों पर कोई संख्यात्मक सीमा नहीं है। छात्रों को अध्ययन के दौरान प्रति सप्ताह कम से कम 20 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अध्ययन के बाद काम करने के अधिकार - एसटीईएम स्नातकों के लिए तीन वर्षों तक और डॉक्टर डिग्री के शोधार्थियों के लिए चार वर्षों तक - बढ़ाए गये हैं।समझौता किसी भी समय 5,000 भारतीय पेशेवरों तक के लिए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीज़ा मार्ग पेश करता है, जिसके तहत आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्माण तथा योग, आयुर्वेद, भारतीय व्यंजन और संगीत शिक्षा जैसे चयनित पारंपरिक क्षेत्रों में तीन वर्षों तक रहने की अनुमति होगी।

चिट्टे के खिलाफ महिलाएं

आमतौर पर नशाखोरी के खिलाफ जब किसी गांव को 'रेड जोन' घोषित किया जाता है, तो यह आधिकारिक तौर पर एक सामाजिक चेतावनी होती है। लेकिन शिमला के कुछ हिस्सों में घोषित यह चेतावनी पुलिस या प्रशासन द्वारा नहीं, बल्कि उन महिलाओं द्वारा जारी की गई है जो परिवारों व समाज को नशे के नासूर से बचाना चाहती हैं। पति हो या बेटा, नशे की हर त्रासदी का त्रास महिलाएं ही भुगतती हैं। वह चाहे किसी अपने को असमय खोना हो या आर्थिक रूप से परिवारिक क्षति हो। यही वजह है कि नशे के खिलाफ अभियान को जमीनी हकीकत बनाने के मकसद से माताएं, बहनें और पत्नियां घर की चैखट से बाहर निकलकर सार्वजनिक रूप से मुखर हुई हैं। महिलाओं के नेतृत्व में चलने वाले इस अभियान को गति देने के लिये सतर्कता समूह बनाये गए हैं। जिसमें नशे के कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिये रात्रि गश्त भी शामिल है। साथ ही नशे की लत के शिकार लोगों को नशामुक्ति केंद्रों तक ले जाने में पहल की जा रही है। निस्संदेह, महिलाएं पुरुष व्यवहार को समझने में खासी संवेदनशील होती हैं। वे नशा करने वाले किसी पारिवारिक सदस्य के व्यवहार में बदलाव, भावनात्मक टूटन व नशे के कारण होने वाली आर्थिक तंगी पर पैनी दृष्टि रखती हैं। उनके व्यक्तिगत अनुभवों के फलस्वरूप वे आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले ही नशे की लत में जकड़े लोगों को पहचानने का प्रयास करती हैं। निस्संदेह, जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे इस अभियान के सार्थक परिणाम आने की उम्मीद जगी है। निर्विवाद रूप से पुलिस व प्रशासन की छापेमारी और गिरफ्तारियां नशे की आपूर्ति पर किसी हद तक अंकुश लगा सकती हैं, लेकिन टूट-बिखर रहे घरों को नहीं बचाया जा सकता। निस्संदेह, नशाखोरी के कई सामाजिक आयाम भी हैं, जिसे सामाजिक स्तर पर पहल करके रोका जा सकता है। रचनात्मक पहल से ही उन कारकों को संबोधित किया जा सकता है जो नशीले पदार्थों को बढ़ावा देते हैं। वाकई सामुदायिक स्तर पर सतर्कता बेहद जरूरी है और महिलाएं इसका नेतृत्व करने में सक्षम भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। सही मायनों में हिमाचल सरकार की 'चिट्टा विरोधी पदयात्रा' और 'महिला मंडलों' की सार्थक पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। निस्संदेह, इस रचनात्मक पहल को संस्थागत स्तर भी समर्थन देने की जरूरत है क्योंकि नशे के कारोबार में संगठित गिरोह भी गहरे तक जुड़े रहते हैं। ऐसे में मादक पदार्थों के तस्करों का सामना करने वाली महिलाओं को अपराधियों की धमकी आदि जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। जिसके लिये सक्रिय पुलिसिंग, गवाहों को सुरक्षा देने, नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास सुविधाएं और लगातार जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता भी होगी।

न्यूज डायरी

एलयू में फीस वृद्धि को लेकर एनएयूआई का प्रदर्शन, कटोरा लेकर मांगी भीख

लखनऊ (यूएनएस)। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर एक बार फिर छात्रों ने प्रदर्शन किया। सोमवार को कैंपस में एनएयूआई से जुड़े स्टूडेंट्स ने कटोरा लेकर भीख मांगी और फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को चंदा सौंपने लगे। मौके पर मौजूद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों से छात्रों की तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इससे पहले एसएफआई ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए फीस वृद्धि वापस लेने की बात कही थी। सोमवार को एनएयूआई से जुड़े छात्रों के गुट ने अचानक से गेट नंबर एक के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान विरोध के रूप में कटोरा लेकर भीख मांगने लगे। अचानक से स्टूडेंट्स को भीख मांगते हुए देख बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह गए। इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। हंगामा बढ़ता देख मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े लोग भी पहुंचे। प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने जब भीख मांग रहे स्टूडेंट्स को रोकना चाहा, तो वो बिफर पड़े। इस दौरान स्टूडेंट्स की प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों से तीखी नोकझोंक भी हुई। इससे बाद गुस्साए स्टूडेंट्स गेट के बीचोंबीच धरने पर बैठ गए। इस दौरान स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों रुपये की फीस लेने के बावजूद छात्रों को दूषित पानी दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स ने दावा किया कि पानी का टीडीएस स्तर 702 पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दोस्त गंभीर

लखनऊ (यूएनएस)। इटौंजा थाना क्षेत्र में सोमवार को इटौंजा-कुर्सी मार्ग स्थित बड़ी नहर के पास एक तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान शिवरी निवासी प्रशांत (26) के रूप में हुई है। बाइक पर पीछे बैठे माधौपुर निवासी दीपचंद (30) गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद केजीएमयू रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डीसीएम चालक बाइक को लगभग 100 मीटर तक घसीटता ले गया। इस दौरान बाइक वाहन के नीचे फंसी रही। टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाराबंकी से प्रशांत के दोस्त अमन के शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फरार डीसीएम चालक की तलाश शुरू कर दी है।

सिटी इंटरनेशनल स्कूल, बालागंज ने भूमि फेस्ट 2026 में बिखेरी चमक'

लखनऊ (यूएनएस)। सिटी इंटरनेशनल स्कूल, बालागंज के विद्यार्थियों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित पर्यावरण विषयों पर आधारित अंतर-विद्यालयी प्रतियोगिता 'भूमि फेस्ट 2026' में अपने उत्कृष्ट प्रतिभा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय ने मॉडल डिस्प्ले श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर सर्वोच्च सम्मान हासिल किया, जो विद्यार्थियों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपलब्धियों में और इज़ाफा करते हुए, फिज़ा मंसूद ने उनके उत्कृष्ट वक्तृत्व कौशल और पर्यावरणीय मुद्दों की गहरी समझ के लिए 'सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। समृद्धि ने भी अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन से विद्यालय का नाम रोशन किया और इस आयोजन में विद्यालय की समग्र सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, प्रबंधक श्री शाह हैदर ने सुश्री व्वाइमा हुसैन और सुश्री भाव्या शुक्ला के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिनकी निरंतर मेहनत और मार्गदर्शन ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके कठिन परिश्रम, उत्साह और समर्पण की सराहना की। विद्यालय परिवार इस उपलब्धि को समग्र शिक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में मना रहा है।

योगी ने फरियादियों की सुनीं समस्याएं, कहा, संवेदनशील होकर समस्याओं का निस्तारण करें अधिकारी

लखनऊ (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प. बंगाल रवाना होने से पहले जनसेवा का संकल्प भी पूरा किया। मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की पीड़ा सुनी और अधिकारियों को संवेदनशील होकर जनता की समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए सभी फरियादियों से मुलाकात की। एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं, प्रार्थना पत्र लिया, फिर अधिकारियों को समय सीमा के भीतर समाधान कराने को कहा। राजस्व व पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हीलाहवाली नहीं चलेगी, समयसीमा के भीतर समस्याओं का समाधान करके पीड़ित को सूचित करना होगा। जनता दर्शन में आए कुछ फरियादियों से मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या जनपद में किसी अधिकारी से मिलकर अपने समस्या बताई? पता चला-नहीं, इस पर मुख्यमंत्री ने फरियादियों से कहा कि बेतहाशा गर्मी में आप परेशान न हों। पहले अपने जनपद में तैनात अधिकारियों से पीड़ा बताएं। हर हाल में सुनवाई होगी और समस्या का यथोचित समाधान भी। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि धूप-गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों पर अपना स्नेह लुटाया। उन्हें चॉकलेट के साथ आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने मां की गोद में बैठे बच्चों से पूछा-चॉकलेट चाहिए तो एक बच्चे ने मुस्कुराकर अभिव्यक्ति दी, इस पर मुख्यमंत्री ने उसे चॉकलेट दी। चॉकलेट पाकर बच्चा खिलखिला उठा।

एडीआरवी लागू होने से वाहनों के खरीद फरोख्त प्रक्रिया ऑनलाइनः दयाशंकर

लखनऊ (यूएनएस)। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रयोग में लाए गए अथवा पूर्व में पंजीकृत मोटर वाहनों की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं डिजिटल माध्यम से सुव्यवस्थित बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम में संशोधन किए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित होंगे। नए नियमों के तहत पंजीकृत वाहन के अधिकृत व्यापारी की व्यवस्था को विधिक मान्यता प्रदान की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रयोग में लिए गए वाहनों के क्रय विक्रय से संबंधित प्रक्रियाएं ऑनलाइन के संपादित होंगी। इससे वाहन स्वामी, अधिकृत डीलर, परिवहन प्रशासन के मध्य उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा।परिवहन मंत्री ने बताया कि पंजीकृत वाहनों के खरीद फरोख्त में संलग्न डीलरों को संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर निर्गत किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र सामान्यतः 5 वर्ष के लिए वैध होगा। साथ ही वाहन स्वामी को भी वाहन के कब्जे एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रमाणिक अभिलेख पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनीं जन-समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए कड़े निर्देश

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने सरकारी आवास, 7 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, किसान और दिव्यांगजन अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें मुख्य रूप से विकास कार्य नाली, खड़ंजा और पेयजल (पानी) की आपूर्ति। प्रशासनिक मामले राजस्व संबंधी विवाद और पुलिस प्रशासन से जुड़ी शिकायतें। आवास योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ में आ रही बाधाएं। आर्थिक सहायता गंभीर बीमारियों के इलाज और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आर्थिक मदद।जनसमस्याओं की गंभीरता को देखते हुए उपमुख्यमंत्री जी ने मौके से ही विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी फतेहपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर और लखीमपुर खीरी। पुलिस प्रशासन पुलिस आयुक्त (वाराणसी), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (आजमगढ़, उन्नाव, रामपुर, कन्नौज)।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों की भूमिका समान-महाना

नेपाली मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने की विधानसभा अध्यक्ष से भेंट

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि भारत और नेपाल के मध्य प्राचीनकाल से ही घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध रहे हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आधार पर निरंतर सुदृढ़ होते रहे हैं।भारत भ्रमण पर आए नेपाल के 20 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के दौरान यह विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष ने कहा कि किसी विषय को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी पूर्ण एवं सत्य जानकारी का परीक्षण आवश्यक है। वर्तमान समय में टीआरपी की प्रतिस्पर्धा के कारण नकारात्मकता को प्रमुखता दिए जाने की प्रवृत्ति चिंताजनक है, जबकि मीडिया का दायित्व समाज में संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।उन्होंने मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र का चैथा स्तंभ बताते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर संसद एवं विधान सभा की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों की समान भूमिका होती है तथा अध्यक्ष दोनों के प्रति समान रूप से उत्तरदायी होता है। उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा पूर्णतः आधुनिक एवं डिजिटल स्वरूप में विकसित हो चुकी है, जहां पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ कार्य संपादित किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने विधानभवन का भ्रमण किया तथा विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया। अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रतिनिधिमंडल को विधानमंडल की कार्यप्रणाली विधि-निर्माण प्रक्रिया एवं

लोकतांत्रिक मूल्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की।प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विभिन्न वषियों पर जिज्ञासाएं व्यक्त कीं, जिनका अध्यक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। उन्हें विधानमंडल की कार्यप्रणाली तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। नेपाल के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहा है।इस अवसर पर प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गाजीपुर में सरकार के इशारे पर हो रहा सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, अखिलेश यादव ने लगाया आरोप

लखनऊ (यूएनएस)। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सरकार के इशारे पर की गई है, और इसमें भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका है। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। अखिलेश ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि गाजीपुर में जो सपा कार्यकर्ता के साथ जो हुआ, वह सरकार के इशारे पर हुआ है और इसमें सरकारी अधिकारियों और भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि उनकी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ खड़ी होकर उन्हें न्याय दिलायें। अखिलेश यादव ने बताया कि विश्वकर्मा समुदाय और पार्टी के सहयोग से धन जुटाकर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही, उन्होंने जानकारी दी कि मंगलवार को पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा और महिला सभा अध्यक्ष सीमा राजभर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। गौरतलब है कि गाजीपुर में 15 अप्रैल को 17 वर्षीय किशोरी का शव गंगा नदी में मिला था। परिजनों ने यौन उत्पीड़न एवं हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। इससे पहले 22 अप्रैल को पीड़िता के परिवार से मिलने गए सपा प्रतिनिधिमंडल पर पथराव हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी है और पीड़िता के गांव में किसी के जाने पर रोक लगा दी है। इस बीच, सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कुछ शरारती तत्व अपुष्ट अफवाहें फैला रहे हैं और विपक्ष मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहा है।

लखनऊ से हज यात्रियों की सातवीं फ्लाइट उड़ी 417 लोग पहुंचे मदीने

लखनऊ (यूएनएस)। लखनऊ में मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का काफिला लगातार रवाना हो रहा है । यात्रियों की 7 वीं फ्लाइट ने उड़ान भरा। 22 अप्रैल को हज यात्रियों की पहली फ्लाइट रवाना हुई थी ये सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। पहले जत्थे को अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज यात्रियों की 7 वीं फ्लाइट रवाना हुई जिस से 417 हज यात्री सऊदी अरब के शहर मदीना पहुंचे इसमें 224 पुरुष और 193 महिलाएं शामिल थी। अब तक हज पर जाने वाले लखनऊ, कानपुर, बहराइच, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़ और सीतापुर समेत विभिन्न जनपदों के यात्री हैं। हज यात्रियों के रुकने की व्यवस्था सरोजिनी नगर स्थित हज हाउस में की गई है। एसपी तिवारी ने कहा कि हज

हाउस में यात्रियों को पूरी सुविधा प्रदान की जा रही है। लखनऊ से जाने वाली फ्लाइट्स में हाजियों की सुविधा के लिए हज इंस्पेक्टर भेजे जा रहे हैं। हज कमेटी में हाजियों के रुकने की भोजन की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए पीने के लिए ठंडा पानी और कमरों में एसी की सुविधा उपलब्ध है। हज हाउस के अंदर कैंटीन की सुविधा है जहां पर रियायती दाम पर भोजन उपलब्ध है। हज हाउस के बाहर मोबाइल टॉयलेट और ट्रैफिक व्यवस्था समेत तमाम चीजों का संपूर्ण रूप से बंदोबस्त किया गया है। यूपी के विभिन्न जनपदों से हज यात्रियों को लेकर आने वाले उनके परिजनों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हज हाउस के अंदर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बाहर भी व्यवस्था की गई है।

रोटरी क्लब लखनऊ ट्रांस गोमती में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का आधिकारिक दौरा सम्पन्न

लखनऊ (यूएनएस)। रोटरी क्लब लखनऊ ट्रांस गोमती में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉ. आशुतोष अग्रवाल का आधिकारिक क्लब दौरा आज गोमती नगर स्थित होटल मर्करी में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। यह अवसर क्लब की कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं समाज सेवा के प्रति उसके संकल्प को और सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। दौरे के दौरान जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक की क्लब गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें रोटरी के 7 प्रमुख फोकस क्षेत्रों एवं 4 सेवा आयामों के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रकल्पों एवं पहलों को प्रदर्शित किया गया, जो समाज के प्रति क्लब की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉ. आशुतोष अग्रवाल ने क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए सदस्यों की टीम भावना, निरंतरता एवं समाज के प्रति उनके सार्थक योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने क्लब द्वारा किए जा रहे सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली प्रकल्पों को अत्यंत सराहनीय बताया।डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने क्लब के वित्तीय विवरण एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की भी समीक्षा की, जिन्हें सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रशंसनीय पाया गया। सभी रिपोर्ट्स

एवं गतिविधियों को अनुमोदन एवं सराहना प्राप्त हुई। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारी अध्यक्ष रोटेरियन पूर्वी मित्तल, सचिव रोटेरियन विनोद सिंह, कोषाध्यक्ष रोटेरियन इला घम्बीर, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन डॉ. पंकज मित्तल,कार्यकारी सचिव रोटेरियन सुधीर एस. हलवासिया और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीण मित्तल उपस्थित रहे।कार्यक्रम का समापन सकारात्मक एवं प्रेरणादायक वातावरण में हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने क्लब को एक सशक्त एवं गतिशील टीम बताते हुए भविष्य में और ऊँचाइयों को प्राप्त करने की शुभकामनाएं दीं। रोटरी क्लब लखनऊ ट्रांस गोमती की अध्यक्ष पूर्वी मित्तल ने कहा कि क्लब समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर बनाए रखते हुए उत्कृष्ट कार्य करता रहेगा।

गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की मांग, युवक को घसीटते हुए ले गई पुलिस

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी में गौ सेवक दीपक कुमार ने सीएम चैराहे पर प्रदर्शन किया। भगवा वस्त्र पहनकर, गले में पोस्टर टांगे दीपक गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन दीपक अपनी मांगों पर अड़े रहे। पुलिस दीपक को घसीटते हुए वहां से ले गई। इस दौरान दीपक ने गौ माता की पीड़ा का मुद्दा उठाया और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। बुलंदशहर के निवासी दीपक ने कहा कि गौ माता की पीड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारी गौ माता स्लॉटर हाउस में और अन्य जगहों पर तड़पती है। आज हम इसीलिए मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने आए हैं कि इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए, और गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु और संत हैं। अगर उनके रहते हुए राष्ट्रीय गौ माता का दर्ज नहीं मिला फिर तो हम लोगों के लिए यह बेहद शर्म की बात होगी। दीपक ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हमारा जीवन गए सेवा के लिए समर्पित है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी गाय जिसे माता मानते है तड़पती हैं , उन्हें आपराधिक मानसिकता वाले लोग अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए पिछले कई सालों से हम गौ माता के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा नहीं दिलवा देंगे तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। आज हम उत्तर प्रदेश के मुखिया से फरियाद करने आए हैं मगर पुलिस हमें सीएम योगी से मिलने नहीं दे रही है। दीपक ने आवाहन करते हुए कहा कि हम अपने सभी सनातन भाई और बहनों से अनुरोध करते हैं कि वह इस मुहिम में हमारा साथ दें। इस लड़ाई को हम राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे यूपी से लेकर दिल्ली तक सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर किसी से मुलाकात करके गौ माता के संरक्षण के लिए कानून बनवाएंगे।

कमता पर ट्रैफिक संभालने उतरीं डीसीपी,नो पार्किंग जोन बनाने के लिए लगी क्रेन

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ में सोमवार को कमता पर बनाए गए नए डायवर्सन प्लान से लोगों को काफी राहत मिली। चैराहे पर बिना रुके वाहन चलते दिखाई दिए। इस दौरान डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी भी सड़क किनारे खड़ी बसों को व अन्य गाड़ियों को हटाती नजर आई। इन रूटों पर लागू हुई व्यवस्था चिनहट से पॉलिटेक्निक,हाईकोर्ट,लोहिया हॉस्पिटल जाने वाले सामान्य यातायात कमता तिराहा से बाएं विजयीपुर सर्विस रोड,विजयीपुर अंडरपास होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे व गोमतीनगर एवं आहिमामऊ जाने वाले सामान्य यातायात शहीद पथ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। पॉलिटेक्निक की तरफ से आने वाला सामान्य यातायात कमता तिराहा के तीसरे अंडरपास से यू-टर्न लेकर शहीद पथ की तरफ जा सकेंगे। पॉलिटेक्निक से हाईकोर्ट,लोहिया हॉस्पिटल जाने वाला सामान्य यातायात राइट टर्न फ्री डिवाइडर

से होते हुए यू-टर्न कर हाईकोर्ट,लोहिया हॉस्पिटल की तरफ जा सकेंगे। बाराबंकी,अयोध्या,गोरखपुर की बसें अवध बस स्टैंड से निकलकर विजयीपुर अंडरपास कठौता, चिनहट होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। चिनहट से हाईकोर्ट,लोहिया हास्पिटल,पालिटेक्निक चैराहा की ओर जाने वाला सामान्य यातायात जीएस लानध्मिनी स्टेडियम कटिंग से कमता फ्लाईओवर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। कमता तिराहे से गुजरने वाले ओवरब्रिज पर ट्रैफिक का संचालन वन-वे है। चिनहट की तरफ आने वाले वाहन ओवरब्रिज से गुजरते हैं। इस ओवरब्रिज पर ट्रफिक संचालन टू-वे होने से कमता तिराहे पर ट्रैफिक लोड़ कम किया जा सकता है। मॉनीटरिंग के बाद डीसीपी रवीना त्यागी का आंकलन है कि पॉलीटेक्निक की ओर से 40 फीसदी ट्रफिक कमता तिराहे से गुजरता है। जबकि चिनहट से पॉलीटेक्निक की 15 फीसदी ट्रैफिक आता है।कमता तिराहे पर ट्रैफिक लोड के अलावा सवारी वाहन, डग्गमार वाहन और रोडवेज बसें पार्क रहती हैं। जिसकी वजह से तिराहा और आस-पास का मार्ग संकरा हो जाता है। तिराहे से सौ-डेढ़ सौ मीटर की दूरी तक मार्ग नो पार्किंग जोन और नो स्टॉप जोन घोषित होने से ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है। कमता तिराहे पर ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए कई बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। वाहन चालकों को आगह करने के लिए तिराहे पर यू-टर्न के बैनर लगाए गए हैं।

योगी सरकार का बड़ा अभियान, हर कार्यस्थल होगा महिलाओं के लिए सुरक्षित

लखनऊ (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान ने प्रदेशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013 (पॉश' एक्ट के प्रावधानों के प्रति प्रतिभागियों और आमजन को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता अभियान में सरकारी-निजी कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य, कॉलेज छात्राएं, अधिवक्ता, श्रमिक संगठन और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सशक्तीकरण मुहिम का हिस्सा यह अभियान कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 पॉश और कामकाजी महिलाओं के वित्तीय-कानूनी अधिकारों पर केंद्रित है, जो नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में नया आयाम जोड़ रहा है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत 'पॉश' अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। अधिनियम कार्यस्थल पर शारीरिक, मौखिक या गैरमौखिक आचरण को, जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में परिभाषित करता है। दस से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जबकि जिला स्तर पर स्थानीय समिति शिकायतों की सुनवाई करती है। शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा तीन महीने है, आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। यह अधिनियम महिला की गोपनीयता की रक्षा करता है, दोष सिद्ध होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या जुर्माना करने का नियोक्ता को अधिकार है। नियोक्ता का दायित्व है कि कार्यस्थल सुरक्षित बने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हों और समिति की सिफारिशों का पालन हो।अभियान में 'पॉश' अधिनियम के अलावा कामकाजी महिलाओं के वित्तीय और कानूनी अधिकारों पर भी चर्चा की जा रही है।

डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थी नहीं सम्मिलित हो सकेगें जूनियर इंजीनियर्स की लिखित परीक्षा में

लखनऊ (यूएनएस)। उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ की डिविजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स अभ्यर्थी ही भर्ती हो सकेंगे। मा0 न्यायालय ने डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों को जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती हेतु अपात्र माना है। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर के 4612 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स को ही आवेदन करने हेतु पात्र बताया गया था। डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों द्वारा इस विज्ञापन को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। अंतरिम राहत न मिलने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत देते हुए डिग्री होल्डर्स को आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया तथा अंतरिम आदेश का विरोध किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को मा0 उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय में महासंघ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया। विस्तृत सुनवाई के बाद मा0 उच्च न्यायालय ने डिग्री होल्डर्स की रिट याचिका डिस्मिस कर दी तथा अंतरिम आदेश समाप्त कर दिया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा सार्ट लिस्टिंग करते हुए डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का आदेश पारित किया। डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों द्वारा पुनः आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की। इस याचिका में डिग्री होल्डर्स ने 13 अभियंत्रण विभागों की सेवा नियमावली को भी चुनौती दिया। उ0 प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा इस याचिका का विरोध किया गया। इं0 एन0डी0 द्विवेदी प्रान्तीय अध्यक्ष डि0इं0सं0 लोक निर्माण विभाग को मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में महासंघ की तरफ से प्रभावी पैरवी हेतु अधिकृत किया गया। इं0 एन0डी0 द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र नाथ मिश्र के माध्यम से मा0 न्यायालय में अपना पक्ष प्रभावी तौर रखवाया। डिविजन बेंच ने विस्तृत सुनवाई के उपरान्त डिप्लोमा के पक्ष में निर्णय देते हुए डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों की याचिका को निरस्त कर दिया।

बसपा के पुराने चेहरों के सहारे पीडीए को मजबूत करने में जुटी सपा

2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की तेज

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पुराने और अनुभवी चेहरों को साथ जोड़कर नई राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी के सूत्रों की मानें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में यह रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सपा के एक सांसद ने बताया कि पार्टी का मानना है कि बी आर अंबेडकर और कांशी राम की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बसपा के पुराने नेताओं को साथ लाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से सपा लगातार ऐसे चेहरों को जोड़ रही है, जो कभी बसपा की जमीनी ताकत रहे हैं और सामाजिक समीकरणों की गहरी समझ रखते हैं। सूत्रों की मानें तो दरअसल, सपा की पीडीए रणनीति का मुख्य आधार यही पुराने बसपा नेता बन रहे हैं। इन नेताओं ने न केवल इस रणनीति को वैचारिक मजबूती दी है, बल्कि इसे जमीन पर उतारने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें इंद्रजीत सरोज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, त्रिभुवन दत्त और ददूदू प्रसाद जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जिन्होंने बसपा

संस्थापक कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, सपा का लक्ष्य 2027 में सत्ता में वापसी करना है, क्योंकि वर्तमान समय में बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में सपा इस खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव जी का पीडीए का फार्मूला इसी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा के रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। 1993 का गठबंधन दोनों दलों के लिए फायदेमंद साबित हुआ था, लेकिन बाद में दोनों अलग-अलग रास्तों पर चले गए। इसके बाद 2019 में फिर से गठबंधन हुआ, मगर अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद सपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सामाजिक समीकरणों पर नए सिरे से काम शुरू किया। सपा अब दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के व्यापक गठजोड़ पर जोर दे रही है। पार्टी नेताओं के अनुसार इसके लिए बसपा के पुराने नेताओं को साथ जोड़ना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का मानना है कि ये नेता जमीनी स्तर पर जातीय समीकरणों को साधने में सक्षम हैं। हालाकि इस रणनीति के सकारात्मक संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले, जहां सपा को बेहतर प्रदर्शन हासिल हुआ। यही वजह है कि पार्टी अब इस मॉडल को और विस्तार देने में जुटी है।

त्वरित आर्थिक सहायता और न्याय का अनूठा उदाहरण, मात्र एक सप्ताह में ही पीड़ित परिवारजन को मिली मदद

जौनपुर। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र के द्वारा जनसुनवाई के दौरान आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में एक सप्ताह पूर्व जनसुनवाई के दौरान तहसील मडियाहूं अंतर्गत विकासखंड बरसठी के ग्राम भदराव निवासी स्व0 मुलायम बनवासी के गेहूं मडाई के दौरान हाथ में बंधा रक्षा धागा थ्रेशर मशीन में फंसने से अत्यंत दुखद मृत्यु का प्रकरण संज्ञान में आया। जिलाधिकारी ने मृतक के परिवारजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक की पत्नी पूजा को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने इस मार्मिक घटना की जानकारी होने पर तत्काल उप जिलाधिकारी मड़ियाहूँ तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शीघ्र अति शीघ्र मृतक के परिजनों को शासन द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश दिए गए।जिसके क्रम में आज जनसुनवाई के दौरान मात्र एक सप्ताह के भीतर ही जिलाधिकारी द्वारा मृतक स्व0 मुलायम बनवासी की पत्नी पूजा को कृषक दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत रु0 5 लाख की सहायता राशि, आवास आवंटन स्वीकृति प्रमाण-पत्र, कृषि पट्टा का स्वीकृति प्रमाण-पत्र, निराश्रित महिला पेंशन योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र, तथा अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किया गया। पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन कराया गया तथा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही परिवारजन को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, राष्ट्रीय परिवारिक आय योजना, बच्चों की शिक्षा हेतु बाल सेवा योजना सहित अन्य योजनाओं से आच्छादित करने हेतु पात्रता की जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के प्रकरण में मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवारजन को तत्काल शासन की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा पात्रता की जांच करते हुए योजनाओं के लाभ से भी आच्छादित किया जाए।जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर पीड़ित परिवार को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराई जाए। मृतक की पत्नी तथा परिवारजन द्वारा त्वरित सहायता और न्याय मिलने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान परिवारजन द्वारा भावुक होकर अवगत कराया गया कि घटना के पश्चात अभी हाल ही में ईश्वर की कृपा से मृतक की पत्नी को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि एक और जहां परिवार एक अपूरणीय क्षति से गुजर रहा है, वही नवजात शिशु का आगमन आपके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आया है।

बोर्ड की बैठक में 39 करोड़ के प्रस्ताव पर लगी मुहर

बदलापुर/जौनपुर। नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में सोमवार को बोर्ड की बैठक अध्यक्ष सीमा सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सर्वसम्मति से 39 करोड़ के अनुमानित बजट पर स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में नगर की सीमाओं पर स्वागत द्वार के साथ नामकरण महाराणा प्रताप, भगवान परशुराम, अशोक सम्राट, एपीजे अब्दुल कलाम किए जाने तथा इंदिरा चौक की चारों सड़कों का नामकरण सल्तनत बहादुर, महाराणा प्रताप, परशुराम व आम्बेडकर मार्ग का बोर्ड लगाए जाने पर सभासदों ने सहमति प्रदान की। इसके अलावा वार्डो में सार्वजनिक स्थलों पर बेंच, सभासदों के नाम का बोर्ड फोटो सहित, मार्गों पर प्रकाश हेतु स्काई लिफ्टर, चार सौ व ढाई सौ केवीए के मोबाइल ट्रांसफार्मर क्रय किए जाने आदि प्रस्तावों पर सहमति बनी।विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने कहा कि नगर पंचायतों के विकास के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है। जो भी काम प्रस्तावित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि सभी वार्डों का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। अधिशासी अधिकारी अलका मौर्या ने सभी का स्वागत तथा संचालन वरिष्ठ लिपिक प्रवेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर वैभव सिंह, हरीलाल, मोदनवाल, चंद्रशेखर निगम, संदीप सिंह, लक्ष्मण सिंह, दिलीप शर्मा, पुष्पा सरोज, सुशील उपाध्याय आदि मौजूद थे।

महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा का जनसंपर्क अभियान तेज, मीना चौबे ने किया बड़ी भागीदारी का आह्वान

वाराणसी चौबेपुर थाना क्षेत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित काशी दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा की प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने चौबेपुर क्षेत्र के ग्राम सभा शाहपुर, बीकापुर एवं सोनबरसा में महिलाओं के साथ घर-घर जाकर संपर्क किया और बरेका में आयोजित होने वाली महिला रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया।मीना चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को अधिकार और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित महिला रैली महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी जरूरी है।उन्होंने महिलाओं से एकजुट होकर आगे आने की अपील करते हुए कहा कि देश की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जिसे अब बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं, तो राजनीति में उनकी बराबर की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रदेश मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष का रवैया निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई काशी से लेकर संसद तक जारी रहेगी और जब तक उन्हें उनका पूरा अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और आगामी रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ज़िला महामंत्री पवन चौबे,ज़िला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जित्तू ,पूर्व प्रधान मोहन राजभर,चिंता राजभर,पार्वती राजभर,मंजू सिंह ,पूनम श्रीवास्तव,संगीता देवी,सुनीता देवी,मण्डल कोषाध्यक्ष स्याम ,अनिल ,मोनू आदि लोग रहे।

निष्पक्षता और पारदर्शिता की मिसालः चंदौली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न

स्वदेश भारत न्यूज़ ब्यूरो

वाराणसी। जनपद चंदौली में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का दूसरे दिन का आयोजन पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशासन की सख्ती और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के चलते सभी परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन और व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। जनपद के कुल 11 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में प्रथम पाली में 4128 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 3033 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जबकि 1095 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में भी उत्साहजनक उपस्थिति देखने को मिली, जहां 4128 के सापेक्ष 3105 परीक्षार्थी शामिल हुए और 1023 अभ्यर्थी अनुपस्थित दर्ज किए गए। पूरे परीक्षा आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी रखी गई, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकी। यह सफल आयोजन प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अभ्यर्थियों ने भी संतोष व्यक्त करते हुए परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बताया। जनपद में इस तरह के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति और सही रणनीति के साथ किसी भी बड़ी परीक्षा को बिना किसी व्यवधान के सफल बनाया जा सकता है।

पति के बाद अब भाई को भी दी मुखाग्नि, जौनपुर की महिला ने पेश की साहस और रिश्तों की मिसाल

जौनपुर। समाज में जहां पारंपरिक मान्यताएं अक्सर महिलाओं की भूमिका को सीमित करती रही हैं, वहीं जौनपुर की एक महिला ने साहस, कर्तव्य और रिश्तों की गहराई का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो लंबे समय तक याद किया जाएगा।नगर रसमंडल मच्छरहट्टा निवासी सुश्री अंजू पाठक ने एक बार फिर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपने सगे भाई संजय कांत तिवारी के निधन पर उन्हें मुखाग्नि देकर भाई-बहन के रिश्ते को नई परिभाषा दी। इससे पहले, लगभग 13 वर्ष पूर्व अपने पति रज्जन पाठक की मौत होने के बाद उन्होंने नगर के रामघाट पर स्वयं उनका अंतिम संस्कार कर समाज में एक अलग मिसाल कायम की थी। उनके भाई संजय कांत तिवारी का आकस्मिक निधन हो गया। वे 56 वर्ष के थे और काशी विद्यापीठ, वाराणसी से शिक्षित थे। अविवाहित संजय कांत तिवारी ने अपने जीवन को परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। वर्ष 2013 में बहन अंजू पाठक के पति के निधन के बाद उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और निष्ठा के साथ उसका निर्वहन किया।उन्होंने अपने भांजे के साथ मिलकर पारिवारिक व्यवसाय को न केवल संभाला, बल्कि उसे आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके व्यक्तित्व में सादगी, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा साफ झलकती थी।भाई के निधन के बाद जब परिवार में कोई अन्य पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, तब अंजू पाठक ने एक बार फिर साहस दिखाते हुए सभी धार्मिक विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। रामघाट पर उन्होंने स्वयं अपने भाई को मुखाग्नि दी। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भावुक कर देने वाला था और हर किसी की आंखें नम हो गईं।स्थानीय लोगों का कहना है कि अंजू पाठक ने जिस हिम्मत और दृढ़ता के साथ दोनों बार अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई, वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की सच्चाई और कर्तव्य किसी लिंग की मोहताज नहीं होती।अंजू पाठक का यह कदम न केवल पारिवारिक जिम्मेदारी का उदाहरण है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनके सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन गया है।ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

पूर्वांचल से पुणे तक रफ्तार का नया अध्यायः अमृत भारत एक्सप्रेस का भव्य शुभारम्भ, यात्रियों को मिलेगी सस्ती और सुविधाजनक सफर की सौगात

स्वदेश भारत न्यूज़ ब्यूरो

वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 26 अप्रैल 2026 को रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनारस से हडपसर (पुणे) के बीच प्रतिदिन चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत का ऐलान किया है। इस सेवा का शुभारम्भ 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को 02531 बनारस-हडपसर (पुणे) अमृत भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी के रूप में किया जाएगा। यह एक गैर-वातानुकूलित प्रीमियम ट्रेन है, जिसे आम यात्रियों के लिए आरामदायक, सुरक्षित और किफायती यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। उद्घाटन विशेष गाड़ी बनारस से शाम 16:45 बजे प्रस्थान करेगी और अपने निर्धारित मार्ग पर प्रमुख स्टेशनों–ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर, गोविंदपुरी, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड कॉर्ड लाइन होते हुए तीसरे दिन रात 00:55 बजे हडपसर (पुणे) पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 08 शयनयान श्रेणी, 11 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 02 एस.एल.आर.डी. कोच तथा 01 पैंट्री कार शामिल होगी। यह संयोजन यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर सुविधा और आराम प्रदान करेगा।अमृत भारत एक्सप्रेस का यह नया संचालन न केवल पूर्वांचल को महाराष्ट्र से जोड़ने का मजबूत माध्यम बनेगा, बल्कि रोजगार, व्यापार और आवागमन के नए अवसर भी खोलेगा। यह पहल भारतीय रेल के उस संकल्प को भी दर्शाती है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ हर वर्ग के यात्री को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना प्रमुख लक्ष्य है। यह शुभारम्भ सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि विकास, कनेक्टिविटी और यात्रियों की मुस्कान का एक नया सफर है।

लंका पुलिस की बड़ी कार्रवाईः झपटमारी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, लूट का सामान और बाइक बरामद

स्वदेश भारत न्यूज़ ब्यूरो

वाराणसी में अपराध पर लगाम कसने के अभियान के तहत वाराणसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना लंका पुलिस ने झपटमारी की घटना को सुलझाते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का सामान और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, काशी जोन के अधिकारियों के पर्यवेक्षण और थाना लंका टीम के नेतृत्व में की गई। 25 अप्रैल 2026 को सामने घाट स्थित जजेज गेस्ट हाउस के पास खाली जमीन से दोनों आरोपियों–डब्बू (25 वर्ष) और साहिद उर्फ साहिल (20 वर्ष)–को गिरफ्तार किया गया।घटना 20 अप्रैल 2026 की है, जब बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला का बैग झपट लिया था। बैग में मांग टीका, नथिया, नाक की कील, ईयर रिंग और करीब 20 हजार रुपये मौजूद थे। पीड़िता की शिकायत पर थाना लंका में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वे नशे के आदी हैं और इसी लत को पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि छीने गए सामान को बेचकर मिलने वाले पैसों से वे अपना खर्च चलाते थे। पुलिस ने उनके पास से 01 मांग टीका, 01 नथिया, 01 नाक की कील, 200 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है।इस मामले में थाना लंका पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस सफलता में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम की अहम भूमिका रही, जिसमें कई अधिकारियों और जवानों ने मिलकर इस घटना का सफल अनावरण किया।

सिटी इंटरनेशनल स्कूल, बालागंज ने भूमि फेस्ट 2026 में बिखेरी चमक'

लखनऊ (यूएनएस)। सिटी इंटरनेशनल स्कूल, बालागंज के विद्यार्थियों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित पर्यावरण विषयों पर आधारित अंतर-विद्यालयी प्रतियोगिता 'भूमि फेस्ट 2026' में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय ने मॉडल डिस्प्ले श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर सर्वोच्च सम्मान हासिल किया, जो विद्यार्थियों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपलब्धियों में और इजाफा करते हुए, फिजा मंसूद को उनके उत्कृष्ट वक्तृत्व कौशल और पर्यावरणीय मुद्दों की गहरी समझ के लिए 'सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। समृद्धि ने भी अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन से विद्यालय का नाम रोशन किया और इस आयोजन में विद्यालय की समग्र सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, प्रबंधक श्री शाहब हैदर ने सुश्री क्वाइमा हुसैन और सुश्री भाव्या शुक्ला के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिनकी निरंतर मेहनत और मार्गदर्शन ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

काशी में ऐतिहासिक आगमनः 14 किमी के भव्य रोड शो संग पीएम मोदी का दो दिवसीय दौरा, जनसैलाब से गूंजेगी बनारस

स्वदेश भारत न्यूज़ ब्यूरो

वाराणसी।एक बार फिर ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है, जब नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल, मंगलवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री शाम 4:00 बजे शहर पहुंचकर बरेका ग्राउंड में लगभग 40 हजार महिलाओं से संवाद करेंगे, जो इस दौरे का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। इसके बाद वे रात्रि विश्राम बरेका गेस्ट हाउस में करेंगे। अगले दिन 29 अप्रैल, बुधवार की सुबह 8:00 बजे उनका काफिला डीएलडब्ल्यू से रवाना होगा और लहरतारा पुलिस लाइन, चौकाघाट, लहुराबीर, मैदागिन होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेगा, जहां प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन करेंगे।इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का यह रोड शो अब तक का सबसे लंबा–करीब 14 किलोमीटर–बताया जा रहा है। पूरे मार्ग पर भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है।जानकारी के अनुसार, रोड शो के दौरान पांच प्रमुख स्थानों पर प्रधानमंत्री का विशेष स्वागत किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने की योजना है। यह पहल महिला सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी को दर्शाने वाली मानी जा रही है। शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। काशी की गलियां, सड़कें और प्रमुख चौराहे इस भव्य आयोजन के लिए सजाए जा रहे हैं। हर तरफ उत्साह और तैयारियों का माहौल है, मानो पूरा शहर अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के स्वागत के लिए तैयार खड़ा हो। यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि काशी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करेगा।

आने वाले समय में बाबा साहब का बहुत असर दिखेगा

डॉ0 अवनीश कुमार गौतम

बाबा साहब अपने समय में चुनाव हार गए थे। आज बाबा साहब का इतना प्रभाव है कि उनके नाम पर सरकारें बन सकती हैं और समाप्त भी हो सकती हैं बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की 135 जयंती पर उनको शत् शत् नमन

बाबा साहब डॉ0भीमराव आंबेडकर जी के द्वारा जो रचा हुआ है, वह आज के समय में लोकतंत्र की यात्रा के साथ-साथ विस्तारित और सर्वव्यापी होता जा रहा है। डॉ0 भीम राव आंबेडकर जी ऐसे समय में आए, जब औपनिवेश का समय था, तब उन्होंने वंचित, शोषित समाज के समस्याओं को उठाने का काम किया। बाबा साहब का उस समय जो प्रभाव था, वह आज उससे कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने पूरे समाज को प्रभावित किया और हम देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में बाबा साहब का कद निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। आज के समय में चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी विचारक हो, बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर सबकी जरूरत बन गए हैं। भारतीय समाज की आज जो राजनीति है, उसके अधिकतर हिस्से में बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर का प्रभाव दिख रखा है। वह आज भी समाज को संबोधित कर रहे हैं और इसका सिद्धांत भी हैं और व्यवहार भी। वह समस्या भी बताते हैं और समाधान भी देते हैं, इसलिए आंबेडकर हमारे लोकतंत्र में विचार-व्यवहार में निरंतर साथ खड़े मिलतें हैं। उनके निर्माण में नए-नए रंग जुड़ते जा रहे हैं, जैसे एक तरफ आंबेडकर वाम की जरूरत हैं, तो दक्षिणपंथ की भी जरूरत हैं। वह दलित, शोषित , वंचित समूह की जरूरत तो हैं ही, व्यापक भारतीय राजनीति की भी जरूरत हैं।

समय के साथ- साथ नए-नए तत्व जुड़ते जा रहे हैं। बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित शोषित, वंचित, भारतीय समाज और लोकतंत्र में जो समस्या थी उस पर अनुभव कर गहराई से विचार किया है। बाबा साहब के प्रभाव से दलित, शोषित व वंचित बहुजन समाज के लोग लगातार सचेत और जागरूक होते जा रहे हैं। बाबा साहब के प्रभाव में बहुजन समाज का लोकतांत्रिक मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर है, जब उसका मूल्य बढ़ रहा है, तो सबकी जरूरत भी बढ़ रही है। बहुजन समाज में जागरूकता बढ़ने में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बाबा साहब शिक्षा को बहुत मूल्यवान मानते थे और कहा भी हैं ' शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वो दहाड़ेगा'' उनके अनुसार शिक्षा केवल साक्षरता नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच, चरित्र निर्माण और आत्मविश्वास पैदा करने का जरिया है, जो सामाजिक बुराइयों और जाति व्यवस्था को समाप्त कर सके। इसके अलावा प्रशासन में भी बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी का असर पड़ा है। जो समाज जागरूक, सचेत था,वह शासन-प्रशासन और विकास में अपनी हिस्सेदारी के लिए लगातार प्रयासरत है। यह आज के समय का सच है कि हर जगह वंचितों की हिस्सा देना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जब इतनी हिस्सेदारी मिल रही है, तो दलित या वंचित समूहों में इतनी गरीबी या इतना अभाव क्यों है ? इसकी एक ही वजह है कि शिक्षा का प्रसार अभी उतने गहरे तरीके से नहीं हुआ है। वंचित समूह में अभी तक एक छोटा हिस्सा ही शिक्षित व जागरूक हुआ है। जैसे-जैसे उन तक चेतना पहुंचेगी, शिक्षा पहुंचेगी, उनमें विकास की आकांक्षा भी बढ़ेगी। अच्छे जीवन की कामना की चाह पैदा होगी, जब यह चाह पैदा होगी, तब लक्ष्य प्राप्त

करने की शक्ति भी आएगी।

ऐसे में, बाबा साहब जी का अभी तक जो असर हुआ है, वह बहुत थोड़ा ही है। उनका बहुत बड़ा असर होना शेष है, जब ऐसा होगा, तब यह एक बड़ा खजाना होगा, जिससे भारतीय समाज संपन्न और सजग होगा। जब तमाम वंचितों तक रोशनी पहुंचेगी, तब हमारा लोकतंत्र भी बदल जाएगा। अब सावल उठता है कि जब यह होगा, तो उसके पहले क्या बदलाव होंगे ? वास्तव में ऐसे बदलाव होने भी लगे हैं। वामपंथी पार्टियां और भाजपा,सपा,कांग्रेस अन्य जैसी पार्टी भी बाबा साहब को याद कर रही हैं, उन्हें जरूरी मान रही हैं। अपनी योजनाओं में बाबा साहब को शामिल करके चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जब यह काम करने लगेंगी, तब बाबा साहब का विचार धीरे-धीरे हर जगह फैल जाएगा। उनका विचार फैलेगा, एक समय आएगा, जब गुणात्मक परिवर्तन होगा और तब बड़े बदलाव आएंगे, वंचित,दलित, शोषित ज्यादा बड़े पैमाने पर संगठित होंगे। भारतीय राजनीति में भी बाबा साहब के नए-नए स्वरूप बन रहे हैं। दक्षिण भारत में एक अलग तरह का आंबेडकरवादी आंदोलन है तो महाराष्ट्र में अलग ,तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग हैं। बाबा साहब का एक दृष्टिकोण यह भी देखा जा सकता है कि इन्होंने अपने विचारों से जो चेतना बहुजन समाज में पैदा की, वह अलग से रेखांकित करने योग्य है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब कोई विचारक चला जाता है, तो वह बहुत प्रासंगिक नहीं रह जाता है। एक समय आता है, जब लोग विचारक को भूल जाते हैं। अगर बाबा साहब को हम देखें, तो वह अपने समय में चुनाव हार गए थे, लेकिन आज बाबा साहब का भारतीय राजनीति में इतने समर्थक हैं कि उनके नाम पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उनके नाम पर सरकारें जा सकती है और बन भी सकती है।देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, तब एक तरफ महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ, बाबा साहब भी अलग स्तर पर सक्रिय थे। वह आजादी को व्यापक स्वरूप में देख रहे थे। उनका यह कहना था कि आजादी मिले, तो दलित मुक्ति भी हो, यह नहीं कि आजाद तो हम हो जाएं, लेकिन वंचितों , शोषितों की स्थिति जस की तस रहे। देश की आजादी की लड़ाई में वह भले आगे न दिखे हों, ट्रेन न जलाए हों, नारे न लगाए हों, लेकिन वह आजादी के व्यापक विचार पर काम कर रहे थे। आजादी मिलने के बाद जो भारत बनना था, उस पर चिंतन शुरू कर चुके थे। एक पक्ष यह मानता है कि महात्मा गांधीजी के संदर्भ में उनका विरोध सही नहीं था, लेकिन वंचित-दलितों का तबका यह मानता है कि उस समय यह विवाद होना जरूरी था। बाबा साहब को लगता था कि गांधी जी दलित मुद्दों को ठीक से संबोधित नहीं कर रहे हैं।बाबा साहब आधुनिकतावादी थे, बाहर से पढ़कर आए थे, महात्मा गांधी जी भी बाहर पढ़े थे, लेकिन वह भारतीय रीति-रिवाज,पारंपरिक मन के दायरे में थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि आजादी के बाद सब मिलकर काम करें, बाघ और बकरी भी एक घाट पर मिल जाएं, पर तब बकरी का पक्ष रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए था और यह काम बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। गांधीजी और बाबा साहब का विरोधाभास होना ही था। यह सकारात्मक था, अगर यह नहीं होता, तो भारतीय आजादी भी पूरी नहीं होती। आज महात्मा गांधीजी भी जरूरी हैं और बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर भी।

आज बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर बाबा साहब में दो गुण ऐसे हैं, जो हर भारतीय समाज में सभी के पास होने चाहिए। समानता के प्रति वह प्रतिबद्ध थे, वह हर चीज को समानता की दृष्टि से देखते थे और हर भारतीय में समानता के प्रति आग्रह आज बहुत जरूरी है। दूसरा गुण यह है कि बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ते बहुत थे, उनमें ज्ञान की आकांक्षा बहुत थी। यह एक ऐसा गुण है, जिसकी कमी को आज भारतीय राजनीति में भी सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ज्ञान की आकांक्षा हर किसी में होनी ही चाहिए।

स्वदेश भारत न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक स्वदीश कुमार द्वारा स्वदेश भारत पब्लिकेशन ग्राम कनकपुर पोस्ट फतेहगंज जिला जौनपुर (उ०प्र०) 222132 से मुद्रित एंव प्रकाशित ।
सम्पादक
स्वदीश कुमार
मो0 9628825379
संरक्षक संजय गुप्ता
7860079888
उप संरक्षक- आदित्य मौर्या
प्रधान संम्पादक- राकेश मौर्या
उप संम्पादक – नियामअतुल्ला
समाचार संम्पादक-
विनय कुमार
सह संपादक- तबरेज नियाजी
कार्यकारी सम्पादक
राजेश गौतम, सतीश चौहान
प्रबन्ध संम्पादक –रंजीत कुमार
@-swadeshbharatnews@gmail-com
समस्त वादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा